

/font>

Title: Regarding problems being faced by the Haj Pilgrims.

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Mr. Speaker, Sir, thank you very much for giving me this opportunity...*(Interruptions)*
I have been trying to raise this issue...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Shri E. Ahamed, let me make it clear that there is no debate on this issue. You have promised that you would speak for two minutes on this issue. I am allowing one minute each to you and to the other hon. Member.

...*(Interruptions)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा नहीं है। इन लोगों की एक मांग है। केवल वह सदन के सामने आएगी और यह पांच मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा।

12.27PM.

Re: Problem being faced by Haj Pilgrims

SHRI E. AHAMED (MANJERI): Sir, the Government of India has decided to restrict and regulate the Haj travel subsidy for the Hajjis who are going under the Central Haj Committee. This time there are about 72,000 Hajjis who are going on Haj pilgrimage under the Central Haj Committee. Restriction and regulation of this Rs. 12,000 travel subsidy to Hajjis has created a havoc amongst the Hajjis. It is because when they applied for it, there was no restriction. Now, the Government wants every Haji to submit an affidavit counter-signed by the Notary Public. The Hajjis are going on the 24th of this month. There is a shortage of time. It is impossible for the Haj Committee to collect all these affidavits counter-signed by the Notary Public. If the Hajjis will not be able to go, then the Haj Committee will have to suffer a loss of nearly Rs. 25 crore because they have already made arrangements for accommodation and they have made travel plans and have also given a schedule to Air India and Saudi Airlines. This decision of the Government cannot be implemented under any circumstances.

Sir, therefore, the community largely objects to this and has asked the Government for reconsideration of the withdrawal of travel subsidy. It is because it is unjust, unfair and uncalled for. However, I would like to say that at least for the time being the Cabinet should take a decision to defer the matter for the next Haj because the next Haj is due to commence in February, 2005. Therefore, unless this is done, this would be a great injustice to the Hajjis...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: I am associating the names of all those hon. Members, who are standing, with this issue.

...*(Interruptions)*

SHRI N.N. KRISHNADAS (PALGHAT): Sir, it is a very serious matter...*(Interruptions)* If this decision is implemented, then tens and thousands of Hajjis would not be able to go to perform Haj...*(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी का नाम एसोसिएट कर रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और लगता है कि यह हज यात्रियों को परेशान करने की साजिश है। जो लोग इस वर्ष हज पर जाने वाले थे, उनके प्रार्थना पत्र 25 जुलाई तक आमंत्रित किए गए और सितम्बर के महीने में भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो लोग आयकर दाता हैं, उनको हज पर जाने के किराए में छूट नहीं दी जाएगी। हज करने वालों के लिए तमाम शर्तें लगाई गईं। यह कितना अव्यावहारिक निर्णय है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का आयकर दाता व्यक्ति हज करने जाएगा तो उसकी उड़ान दिल्ली से होगी। उसकी बूढ़ी मां, उसकी पत्नी, उसके बूढ़े बाप, जो आयकर दाता नहीं हैं, उनको लखनऊ से जाना होगा। इसके बारे में न कोई हज कान्फ्रेंस हुई, न मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया। किसी से बात हुई, बगैर लोगों को विश्वास में लिए, बगैर उनके जजबात को समझे सरकार ने यह निर्णय कर लिया है जो किसी भी कीमत पर न तो न्यायसंगत है और न व्यावहारिक है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह जो निर्णय सरकार ने लिया है, यह हाजियों की भावनाओं के बिल्कुल प्रतिकूल है और इसकी हाउस में निन्दा की जानी चाहिए तथा सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए।*(व्यवधान)* मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया ? सरकार को इस निर्णय को तुरंत वापस लेना चाहिए।*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी, आपको बोलने की इजाजत किसने दी है?

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। यह निर्णय बिल्कुल अव्यावहारिक है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।*(व्यवधान)*

MR. SPEAKER: Shri M.O.H. Farook.

SHRI M.O.H. FAROOK (PONDICHERRY): Sir, the Cabinet came out with certain instructions in September to be implemented in the Haj Committee.....(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : एक मैम्बर बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने दिया जाए।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जरा बैठिए। फारुक जी को बोलने दीजिए। वह कई दिनों के बाद बोल रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Farook is speaking after a long time. Let him speak. He is a Member of the Haj Committee.

SHRI M.O.H. FAROOK : Sir, I am a Member of the Central Haj Committee appointed by you. In September, the Cabinet has come out with certain instructions regarding subsidy to be implemented in the Haj season. There are so many legal as well as religious restrictions over this issue. This has created a lot of problems for the Central Haj Committee to implement them.

Another point is, the Central Haj Committee is in no way consulted at any point of time when this restriction has been implemented.

I support all these people. Yesterday, the Minister for Civil Aviation has conducted a meeting and we have placed all our difficulties before him. He has assured that he would take them to the Cabinet. Our plea is that these restrictions should be postponed for the next year and we may go ahead in the same way as you have done earlier. The present Haj activities should continue according to the old plan. This is our pleaâ€¦â€¦ (Interruptions) Application in this regard was given in July and this decision has come out in September. Therefore, this has created a problem.

MR. SPEAKER: Shri Rashid Alvi.

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको इससे एसोशिएट करता हूँ। जो इंकम टैक्स पेयी के लिए कहा गया है कि उनको रिबेट नहीं मिलेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइन्स हैं जो सरकारी रिबेट के बाद टिकट देती हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी एयरलाइन्स हैं जिनको अगर चार्टर किया जाए तो हवाईजहाज का जो टिकट है, वह उससे कम पर होगा। यह एक बहुत गलत फैसला है जिसे सरकार को फौरन वापस लेना चाहिए। इससे बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी।â€¦(व्यवधान) कोई हर्बैंड इंकम टैक्स पे करता है और वाइफ पे नहीं करती तो वाइफ का जाना मुश्किल हो जाएगा और बगैर हर्बैंड के वाइफ हज को नहीं जा सकती।â€¦(व्यवधान) इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हज के मामले में फौरन कदम उठाने चाहिए। जो हाजी इस बार जा रहे हैं, उनके एफीडैविट जमा करने से मुस्तसना करना चाहिए और इस पर दुबारा गौर करके इंकम टैक्स की जो शर्त लगाई गई है, उसे विदड़ों करना चाहिए।â€¦(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : हर बार क्या आप ऐसे ही करेंगे? â€¦(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हज यात्रियों को रिबेट देने के संबंध में जो निर्णय सरकार ने लिया है, उस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और इस निर्णय को फौरन वापस लेना चाहिए।â€¦(व्यवधान)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : हम क्यों नहीं बोलेंगे ? क्या आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा? â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बोलिए।

â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : इनकी भी सुनें, शायद ये आपका समर्थन कर रहे हों। इसलिए इनको सुनना चाहिए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : आपकी सरकार ने हज के लिए जितनी सब्सिडी दी, उससे तीन गुना ज्यादा सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट ने कहा है कि हज के लिए सब्सिडी देना उचित नहीं है, गैर इस्लामिक है इसलिए कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए।â€¦(व्यवधान) जबकि हम तीन गुना ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। कोई भी मुस्लिम देश सब्सिडी नहीं देता। यह गैर इस्लामिक है। जो इंकम टैक्स पे कर रहा है, उसको भी सब्सिडी मिले, यह सवाल उठाना निहायत ही गलत तरीका है।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कोई चर्चा या बहस नहीं हो सकती। आप सब लोग बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस के जमाने में जितनी सब्सिडी मिलती थी, उससे तीन गुना ज्यादा हम दे रहे हैं और यह इसको राजनीतिक सवाल बना रहे हैं।

कोई आदमी इनकम टैक्स पे करता है, क्या उसको भी सब्सिडी दी जाएगी? (ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि. पासवान आप बैठिए। आपके बड़े भाई बैठे हैं और छोटा भाई खड़ा है।

(ब्यवधान)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please sit down for a minute.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Let me make it clear. Please sit down.

...(Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : कोई भी मुस्लिम देश सब्सिडी नहीं देता, जबकि हम तीन गुना ज्यादा दे रहे हैं। (ब्यवधान)

MR. SPEAKER: There is an important Calling Attention notice. As an exception only I allowed this. Shri E. Ahamed has come and told me that this is a very important issue and that there is a time limit within which this issue is to be settled. I permitted three or four hon. Members to speak on this issue. But there cannot be a debate on this issue.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have disallowed all notices.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Hannan Mollah, please do not speak in this manner. You are a nice Member. Please sit down. I cannot permit you to speak. I am not going to permit you to speak.

...(Interruptions)

SHRI HANNAN MOLLAH (ULUBERIA): It is unfortunate. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: It may be unfortunate. I cannot help it. This is not the way in which you can address the Chair. You are a senior Member. You are supposed to understand this. Now, I have stopped discussion on this issue. A number of Members have expressed their feelings. I cannot permit every Member to speak.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: What do you mean thereby? This is not the disciplined behaviour in the House.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: There is a very important debate before me.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra expressed his views.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, you all made a request in this regard and I considered it.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: If you want me to go strictly according to the rules, I will go strictly according to the rules.

...(Interruptions)

श्री रामजीलाल सुमन : ये क्यों जवाब दे रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। देखिए, अगर इस हाउस में डिस्प्लीन नहीं होगा तो मैं स्ट्रीक्टली रूल्स के मुताबिक चलूंगा। विषय महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने उसको यहां उठाने की इजाजत दी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सभी सदस्यों को बोलने की इजाजत दूँ। Please try to understand this.

...(Interruptions)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, this House has seen that this is an emotional issue also. ... (Interruptions)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : शिवराज जी, यह कोई तरीका है ! â€ (ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Let me argue. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have permitted Shri Shivraj Patil to speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will take on record only what Shri Shivraj Patil says. Please sit down.

(*Interruptions*) â€*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, the hon. Member from the Congress Party has made a very valid suggestion. He said that there are many issues involved in this, let them be carefully examined and then a decision be taken. That decision should be made applicable only after a careful examination of all issues involved. He has tried to say that if you apply the principle of excluding the income-tax payers, then also difficulties will arise because only Government

* Not Recorded

servants are paying income tax, others are not paying income tax. So, they will get this benefit. Those people who are paying small amount of income tax will not be able to make use of this facility.

Moreover, this Government, our country, has taken into consideration the religious feelings of the people. That is why Rs.100 crore was given by the Government of India rightly for the Nasik *Kumbhamela*. So, we are considering all the aspects. My submission to the government is that this is an emotional issue. Let it be carefully examined. Let a decision be taken.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : कैलाश मानसरोवर के लिए सब्सिडी नहीं है, पाकिस्तान में गुरुद्वारों के लिए सब्सिडी नहीं है। इनको 175 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद भी सवाल उठा रहे हैं।â€ (ब्यवधान)

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतो कुमार गंगवार) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं से में संबंधित मंत्री जी को अवगत करा दूंगा।

â€ (ब्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप हज के सवाल पर भी कॉलिंग अटेंशन देने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज इस विषय पर नहीं।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, earlier, you assured the House that you would take it up under Calling Attention....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I am taking up Calling Attention.

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूँ। कॉलिंग अटेंशन के लिए नोटिस देना पड़ता है। इस विषय पर कॉलिंग अटेंशन एडमिट करने को मैं तैयार हूँ।

â€ (ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, मंत्री जी आ रहे हैं, राज्य सभा में गये हैं।

â€ (ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कॉलिंग-अटेंशन लेता हूँ।

â€ (ब्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, आपका विषय महत्वपूर्ण होने की वजह से मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है। मंत्री जी राज्य सभा में हैं। वहां से फ्री होने के बाद वे यहां आयेंगे। रघुवंश प्रसाद जी आप बोलिये।

â€ (ब्यवधान)

MR. SPEAKER: I am ready to accept it. There is no problem.

Now, the House will take up Calling Attention. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, बिहार की आठ करोड़ तीस लाख महान जनता की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं और बिहार की आठ करोड़ तीस लाख महान जनता आपकी आभारी है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। रघुवंश जी, आप नियम जानते हैं कि पहले आपको केवल विाय बताना है, बाद में जोरदार भाण देना है। पहले विाय बताइये। मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, तब बाद में आप तकरीर करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आर्थिक पैकेज की आवश्यकता के बारे में **टैट** (व्यवधान)

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): Sir, I am on a point of propriety....(Interruptions) Please listen to me for one minute.

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठ जाइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : आपने रघुवंश जी को पुकारा था।

अध्यक्ष महोदय : रूल के मुताबिक पाइंट ऑफ प्रोपराइटी पहले आती है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठ जाइये।

SHRI G.M. BANATWALLA : Sir, Under Matters under Rule 377, I had made a submission in the House asking the Government to withdraw the conditions on *Haj* subsidy. Now, the Government has replied that it would consider the points raised in the House in the 'Zero Hour.' My point is that my submission made under Rule 377 should also be considered. The conditions on withdrawal of subsidy which are unjustified must be withdrawn. So, that is also to be considered along with the points that are made today. This submission has already been made in detail under Rule 377 by me earlier. ...(Interruptions)

SHRI E. AHAMED : Sir, kindly direct them to make a statement on this subject....(Interruptions)

MR. SPEAKER: That issue is over.
